भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3220

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत इटली संबंध

3220. **श्री दयानिधि मारनः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान हुए समझौते के बाद भारत–मध्य पूर्व यूरोप संपर्क गलियारे (आईएमईसीसी) को क्रियान्वित करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं तथा मंत्रालय किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि इटली इस पहल को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाए;

(ख) आईएमईसीसी के तहत सहयोग के लिए इटली में कौन से विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इस भागीदारी से भारतीय हितधारकों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) भारत और इटली के बीच आर्थिक, रक्षा, और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं;

(घ) क्या इस सुदृढ़ भागीदारी के परिणामस्वरूप कोई नए समझौते/निवेश अपेक्षित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एफएओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे रोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने प्रभाव और योगदान का विस्तार करने की किस प्रकार योजना बना रहा है; और

(च) यूरोप और भूमध्य सागर में एक प्रमुख भागीदार के रूप में इटली पर जोर देते हुए इस द्विपक्षीय संबंध के दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) और (ख) इटली भारत के साथ उन चुनिंदा साझेदारों में शामिल है, जिन्होंने 2023 में दिल्ली में जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान एक नए भारत–मध्य पूर्व– यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) को विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करने की घोषणा की। अन्य साझेदारों में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका शामिल हैं।

आईएमईईसी कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण करना है, में अनेक हितधारक शामिल हैं और यह अभी प्रारंभिक चरण में है।

(ग) (घ)और (च) भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी है। 18 नवंबर 2024 को रियो में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय संबंधों को गति देने के लिए 2025–2029 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (जेएसएपी) की घोषणा की। जेएसएपी के तहत, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, अंतरिक्ष, ऊर्जा संक्रमण, रक्षा, सुरक्षा, प्रवास और गतिशीलता, संस्कृति, शैक्षणिक और लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करेंगे।

(ङ) रोम स्थित तीन संयुक्त राष्ट्र निकायों – खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत वैश्विक कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण तथा ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नीतियों और दृष्टिकोणों को आकार देने के लिए इन संयुक्त राष्ट्र संगठनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। प्रमुख शासी निकायों और समितियों के सदस्य के रूप में भारत इन संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रभावी शासन में योगदान देता है। भारत विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य को भी अभिव्यक्त कर रहा है। इन संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी साझेदारी पहलों और प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास के रूप में विकसित हुई है, जिनकी अन्य विकासशील देशों के लिए अत्यधिक प्रासंगिकता है।

*****